गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PRGI No. UPHIN/25/A1697

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 041
दि. 10.06.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

कुवैत के अमीर से पीएम मोदी की बातचीत, पश्चिम एशिया की स्थिति पर जताई चिंता; तनाव कम करने पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मशाल से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया के बदलते सुरक्षा हालात और बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई तथा कूटनीति के जरिए शांति बहाली पर जोर दिया।

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कुवैत के अमीर शेख मशाल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे सुरक्षा हालात पर विचार-विमर्श किया।

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री ने तनाव कम करने, संवाद और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और उनके कल्याण के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए

कुवैत के अमीर का आभार भी व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद हुई बातचीत

आपको बता दें कि दोनों नेताओं की यह बातचीत कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए उस हमले की भारत द्वारा निंदा किए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। 3 जून को विदेश मंत्रालय ने फिर से कहा कि आम नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। मंत्रालय ने पीड़ित के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा था कि इस इलाके में मौजूद भारतीय मिशन प्रभावित नागरिकों की मदद करने और स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के लिए अलर्ट है।

'निराशा में डूबा था भारत, अब विश्वास से भरा', मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बोले नितिन नवीन

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार 26 मई को अपने 12 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। इसी के साथ नरेन्द्र मोदी चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सबसे लंबा शासन करने वाले बन गए हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के कालखंड को पार कर लिया है। इसे सुशासन का कालखंड बताते हुए भाजपा देशभर में लगातार कार्यक्रम कर रही है।

इसी उपलक्ष्य में भाजपा अध्यक्ष व सांसद नितिन नवीन ने नई दिल्ली में आयोजित संवाद कार्यक्रम में राजग सरकार की उपलब्धियां विस्तार से गिनाईं। पूर्व सरकार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन 2014 से पहले और उसके बाद आए बदलावों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि पहले भारत निराशा में डूबा हुआ था, जबकि आज विश्वास से भरा हुआ है।

भारत मंडपम में मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह,

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए। संगठन की ओर से भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने ही राजग सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया।

उन्होंने दावा किया कि हर घर नल योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने इज्जतघर (शौचालय) और उज्ज्वला योजना ने महिलाओं का जीवन बदल दिया। जो किसान खेती के लिए कर्ज लेते थे, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि से संबल मिला। युवाओं को स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना आदि से आगे बढ़ने का अवसर मिला।

12 साल में हुआ अभूतपूर्व विकास

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से भारत से महिला सशक्तीकरण से लेकर 12 साल में देश में अभूतपूर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास का उन्होंने दावा किया। भाजपा अध्यक्ष ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को प्रधानमंत्री मोदी के सुशासन का मूल मंत्र बताते हुए याद दिलाया कि वैश्विक स्तर पर भारत की धाक बढ़ी है और 32 देशों ने पीएम मोदी को जो सम्मान दिया है, वह 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। उनके वक्तव्य का निष्कर्ष यही था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूर्ण कर चुकी राजग सरकार जन-जन के विश्वास, अंत्योदय के संकल्प और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए समर्पित रही है। इस दौरान एक लघु फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें राम मंदिर निर्माण और ध्वजारोहण से लेकर भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के दृश्य मौजूदा सरकार के संस्कृति से लेकर तकनीकी तक तक के जुड़ाव और समर्पण को दर्शाने के लिए थे।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कश्मीर शांति और स्थिरता के नए युग का गवाहः रक्षा राज्य मंत्री सेठ

श्रीनगर, नौ जून (भाषा) जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की बढ़ती संख्या और फिल्म निर्माण के पुनरुद्धार का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर शांति, स्थिरता और विकास का गवाह बन रहा है।

पुलवामा जिले में 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान' (एम्स) अवंतीपोरा परियोजना की समीक्षा करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, 'पिछले साल 2.41 करोड़ पर्यटक जम्मू-कश्मीर आए थे, जबकि इस साल अब तक 1.77 करोड़ पर्यटक यहां का दौरा कर चुके हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि पहले अधिकतर फिल्मों की

शूटिंग कश्मीर में होती थी, लेकिन (1980 के दशक के उत्तरार्ध में अशांति के बाद) इस संख्या में गिरावट आई। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा, 'लेकिन अब, इसमें फिर से उछाल आया है।' सेठ ने बताया कि पिछले साल घाटी में 400 फिल्मों की शूटिंग की गई थी। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा, 'प्रधानमंत्री हमेशा कश्मीर और पूर्वोत्तर का दौरा करने पर जोर देते हैं। हमारा भारत एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक।' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह 1970 के दशक से लगातार कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया, 'उस दौर के कश्मीर और आज के कश्मीर में बहुत बड़ा अंतर है।

यहां बहुत बड़े पैमाने पर विकास हुआ है और इस मामले में पिछले 12 वर्ष अतुलनीय रहे हैं।' सेठ ने कहा कि हाल के वर्षों में क्रिकेट बल्ला उद्योग भी खूब फला-फूला है।

कांग्रेस को तगड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हुआ रद्द, क्या भाजपा को होगा फायदा?

(जीएनएस)।

राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच प्रक्रिया के दौरान रद्द कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक, मीनाक्षी नटराजन पर आरोप है कि उन्होंने नामांकन दाखिल करते समय अपने खिलाफ हैदराबाद में लंबित एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई हलफनामे में उसका उल्लेख नहीं किया।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आने पर उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। इस फैसले ने कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है और पार्टी के लिए इसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।

मामले की शुरूआत 11 मई 2025 को कथित घटना से हुई थी। इसके बाद 20 अगस्त 2025 को

शिकायतकर्ता ए. श्रीलता ने हैदराबाद की चौथी अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी अदालत में मीनाक्षी नटराजन समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (इठर) की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए।

अदालत ने जारी किया था समन

मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने 17 सितंबर 2025 को मीनाक्षी नटराजन को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 24 अक्टूबर 2025 को उनके वकील ने अदालत में जवाब दाखिल करते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया और इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित मामला करार दिया।

17 नवंबर 2025 को हुई सुनवाई में अदालत ने मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया और नियमित सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि यह मामला अभी भी अदालत में लंबित है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिलिपींस के मिंदनाओ में भूकंप से हुई जानमाल की क्षति पर दुख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिलिपींस के मिंदनाओ में आज भूकंप से हुई जानमाल की क्षति पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने इस हादसे के मृतकों के परिवारजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करने के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि फिलिपींस की अवाम और सरकार के साथ भारत एकजुटता से खड़ा है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखाः "फिलिपींस के मिंदनाओ में आज भूकंप से हुई जानमाल की क्षति से मुझे दुख पहुंचा है। मैं मृतकों के परिवारजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।

दिल्ली की सड़कों का होने वाला है डिजिटल इलाज! ट्रैफिक-जलभराव पर एक साथ वार करेगी रेखा सरकार की नई योजना

(जीएनएस)।

दिल्ली में ट्रैफिक जाम, टूटी सड़कें, धूल से होने वाला प्रदूषण और बरसात के दौरान जलभराव लंबे समय से लोगों की परेशानी का कारण रहे हैं। अब दिल्ली सरकार इन समस्याओं से निपटने के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है, जो सिर्फ गड्ढे भरने या सड़क मरम्मत तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पूरी सड़क व्यवस्था को डिजिटल और वैज्ञानिक तरीके से मॉनिटर करेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार (09 जून) को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी में पहली बार रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (RAMS) विकसित किया जा रहा है।

दिल्ली की सड़कों के लिए नया ब्लूप्रिंट

सरकार ने इस परियोजना के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI) और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) के साथ समझौता किया है। इस साझेदारी का मकसद दिल्ली की सड़कों के रखरखाव को पारंपरिक व्यवस्था से निकालकर डेटा आधारित और वैज्ञानिक मॉडल पर लाना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और वाहनों की संख्या ने सड़क प्रबंधन को पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में अब सड़कों की स्थिति का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में तैयार किया जाएगा और उसी आधार पर मरम्मत तथा रखरखाव की प्राथमिकताएं तय होंगी।

कैसे काम करेगा नया सिस्टम?

रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत राजधानी की सड़कों का विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसमें सड़क की स्थिति, उसकी उम्र, क्षतिग्रस्त हिस्सों और मरम्मत की जरूरत से जुड़ी जानकारी दर्ज होगी।

इसके बाद नियमित अंतराल पर सड़कों का मूल्यांकन किया जाएगा। इससे यह तय करना आसान होगा कि किस सड़क को पहले मरम्मत की जरूरत है और कहां संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि इससे सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होगा और अनावश्यक खर्च भी कम होगा।

धूल-मुक्त दिल्ली का सपना

इस योजना का एक बड़ा लक्ष्य दिल्ली को धूल प्रदूषण से राहत दिलाना भी है। राजधानी की सड़कों के किनारे वैज्ञानिक तरीके से ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधों और पेड़ों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे।

इसके साथ ही टिकाऊ लैंडस्केपिंग, हरित अवसंरचना और पर्यावरण-अनुकूल डिजाइन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि सड़कों के किनारे हरियाली बढ़ने से धूल नियंत्रण में मदद मिलेगी और शहर का वातावरण भी बेहतर होगा।

जलभराव से भी मिलेगी राहत?

दिल्ली में हर मानसून के दौरान कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आती है। नई योजना में सड़कों की ढलान और स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम को फिर से डिजाइन करने पर भी जोर दिया गया है।

सरकार का दावा है कि बेहतर जल निकासी व्यवस्था के जरिए बारिश के दौरान सड़कों पर पानी जमा होने की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। इसके अलावा वर्षा जल संचयन को भी इस परियोजना का हिस्सा बनाया गया है।

'पीएम मोदी खुद रख रहे हैं 'नीट' पर नजर' शिक्षा मंत्री ने छात्रों को दिया भरोसा, कहा- समय पर आएगा रिजल्ट

(जीएनएस)।

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर पिछले कुछ वर्षों में हुए विवादों, पेपर लीक के आरोपों और परीक्षा प्रक्रिया पर उठे सवालों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी थी। पिछले साल सामने आए मामलों के बाद सरकार पर भी परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का दबाव था। अब ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस बार किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती।

यही वजह है कि परीक्षा की तैयारियों को लेकर सरकार ने कई स्तरों पर सुरक्षा और निगरानी का बड़ा तंत्र तैयार किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अचानक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (ठळअ) मुख्यालय पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ लंबी समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस बार परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और समय-समय पर तैयारियों की जानकारी ले रहे हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गंभीर हैं क्योंकि यह परीक्षा सीधे तौर पर लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि परीक्षा आयोजन से जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू पर उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

सरकार का मकसद केवल परीक्षा कराना नहीं, बल्कि ऐसा माहौल तैयार करना है जिसमें छात्र बिना किसी डर, संदेह या विवाद के परीक्षा दे सकें। यही कारण है कि इस बार सुरक्षा और निगरानी को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत बनाया गया है। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि परीक्षा व्यवस्था को लेकर कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें कई मंत्रालयों और एजेंसियों ने हिस्सा लिया है।

सरकार ने नीट परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए केवल शिक्षा मंत्रालय पर निर्भर रहने के बजाय दूसरे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को भी इसमें शामिल किया है। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक वे खुद गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। प्रश्नपत्र तैयार होने के समय से लेकर उसके परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को कड़ी सुरक्षा के दायरे में रखा गया है।

कौन है वो बीजेपी नेता जिसके एक लेटर से हिल गई पूरी कांग्रेस, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, राहुल गांधी की हैं खास

मध्य प्रदेश में मंगलवार को बड़ी सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। बीजेपी की आपत्ति के बाद कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज हो गया है।

(जीएनएस)।

भोपालः एमपी में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बीजेपी की आपत्ति के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने यह फैसला लिया है। मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की करीबी नेता मानी जातीं है। मंगलवार को बीजेपी ने आपत्ति लगाई थी जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया था। मीनाक्षी नटराजन का पक्ष जानने के बाद उनका नामांकन रद्द किया गया है।

राहुल कोठरी ने लगाई थी आपत्ति

बीजेपी नेता राहुल कोठारी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को चुनौती दी थी। रिटर्निंग ऑफिसर को लिखे लेटर में राहुल कोठारी ने कहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपने शपथ पत्र में जानकारी छिपाई है। रिटर्निंग ऑफिसर को भेजे गए लेटर में राहुल कोठरी ने लिखा- राज्यसभा निर्वाचन 2026 के लिए अपनी नामांकन और शपथ पत्र में मीनाक्षी नटराजन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की जाती है। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि हैदराबाद के एक केस का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 356, 61, 45 , 46, 315 (2) और 79 आरोपित की गई हैं। नामांकन के समय यह प्रकरण अस्तित्व में था जिसका शपथ पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है।

कौन हैं राहुल कोठारी

राहुल कोठरी एमपी बीजेपी के नेता हैं। मौजूदा समय में वह प्रदेश महामंत्री हैं। इससे पहले वह संगठन में अलग-अलग जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। राहुल कोठारी पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं।

राहुल गांधी की हैं खास

कई दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था। मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की टीम का हिस्सा हैं। वह मंदसौर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुकी हैं। मीनाक्षी नटराजन वर्तमान समय में तेलंगाना की कांग्रेस प्रभारी हैं।

सम्पादकीय

क्या देश में आ रही चुनौती जनसंख्या बढ़ाने की

आज भारत के सामने चुनौती जनसंख्या बढ़ाने या घटाने की नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था र्निमित करने की है जिसमें नागरिक आने वाले कल से भयभीत न हो। क्योंकि जहां भविष्य पर विश्वास होता है, वहां बच्चे बोझ नहीं, आशा बनकर जन्म लेते हैं और जहां भविष्य ही असुरक्षित हो, वहां घटती जन्मदर आंकड़ा नहीं, व्यवस्था पर लिखा हुआ एक मौन अभियोग बन जाती है।

रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। रोटी के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए शिक्षा चाहिए और शिक्षा के लिए धन चाहिए। कपड़े सस्ते भी पहने जा सकते हैं, लेकिन मकान सस्ता नहीं मिलता। यही वह कठोर यथार्थ है जिसके बीच आज का भारतीय परिवार अपने भविष्य का गणित बैठा रहा है। इसलिए भारत में जनसंख्या का प्रश्न अब केवल जन्मदर का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता और संसाधनों की उपलब्धता का प्रश्न बन चुका है।

भारत की जनसँख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.7 प्रतिशत है, जबकि पृथ्वी के वुल भूभाग का मात्र 2.4 प्रतिशत हिस्सा ही भारत के पास है। यह असंतुलन अपने आप में बहुत वुछ कह देता है। भूमि सीमित है, जल सीमित है, संसाधन सीमित हैं, कितु उन पर निर्भर लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भले ही वुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुँच चुकी हो और जनसंख्या वृद्धि की गति मंद पड़ रही हो, कितु वास्तविक जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है। अर्थात प्रतिशत घट रहा है, पर संख्या बढ़ रही है। यही भारत की जनसांख्यिकीय विडम्बना है।

संसाधनों पर बढ़ता दबाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। महानगरों में लाखों लोग एक कमरे के मकानों में जीवन बिताने को विवश हैं। जमीन के दाम सामान्य नागरिक की पहुँच से बाहर हो चुके हैं। एक मध्यमवगाय परिवार अपने जीवन की आधी से अधिक कमाई केवल एक छोटे से घर के लिए खर्च कर देता है। घर खरीदना आज आवश्यकता से अधिक एक संघर्ष बन चुका है।

युवा नौकरी मिलने के बाद विवाह की नहीं, पहले मकान की चिता करता है। उसके बाद बच्चों की शिक्षा का प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है।

आज शिक्षा भी एक महँगा निवेश बन चुकी है। अभिभावक जानते हैं कि केवल बच्चे को जन्म देना पर्याप्त नहीं है। उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी होगी, प्रतिस्पधा परीक्षाओं की तैयारी करानी होगी, तकनीकी कौशल उपलब्ध कराना होगा और फिर रोजगार की अनिाित दुनिया में उसे स्थापित करना होगा। ऐसे में समझदार और शिक्षित परिवार बच्चों की संख्या नहीं, उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं। यह केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि आर्थिक विवशता का परिणाम है।

रोजगार की स्थिति भी जनसंख्या विमर्श को प्रभावित कर रही है। स्थायी नौकरियों का स्थान संविदा आधारित नियुक्तियों ने ले लिया है। लाखों युवा आधे वेतन में दोगुना काम कर रहे हैं। उनके सिर पर हर वर्ष अनुबंध नवीनीकरण की तलवार लटकती रहती है। भविष्य अनिाित है, पेंशन का भरोसा नहीं है और सामाजिक सुरक्षा का ढाँचा कमजोर है। जो व्यक्ति स्वयं अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं है, वह कई बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठाने का साहस वैसे करेगा? यह स्थिति केवल युवाओं तक सीमित नहीं है। भारत तेजी से वृद्ध समाज की ओर भी बढ़ रहा है। वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कितु उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाएँ विकसित नहीं हो पा रही हैं। मेट्रो में बैठने की वुछ आरक्षित सीटें उनकी बढ़ती संख्या के सामने अपर्याप्त हैं। रेलों में आकस्मिक यात्रा करने वाले बुजुर्गो को आरामदायक बर्थ मिलना कठिन होता जा रहा है। कोविड काल के बाद रेलवे किराये में मिलने वाली रियायतें भी समाप्त हो गईं। स्वास्थ्य सुविधाएँ महँगी होती जा रही हैं और वृद्धावस्था की चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। प्रश्न यह भी है कि आने वाले वर्षो में इन बुजुर्गो की देखभाल कौन करेगा? वह युवा, जो स्वयं अस्थायी रोजगार, महँगी शिक्षा, बढ़ते किराये और सीमित आय के बीच संघर्ष कर रहा है? संयुत्त परिवारों का विघटन हो चुका है। सामाजिक सुरक्षा का भार परिवारों पर है और परिवार स्वयं आर्थिक दबावों से जूझ रहे हैं।

लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (विनिमय) का उद्घाटन

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (विनिमय) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव और लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लैंड पोर्ट अथॉरिटी को नई दिशा मिली। सुरक्षा-केंद्रित सोच से आगे बढ़कर लैंड पोर्ट को सुरक्षा के पहले कवच, व्यापार सुगमता के माध्यम और लोगों के बीच संपर्क सेतु के रूप में विकसित किया गया। साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास, वैध व्यापार को बढ़ावा देने और सीमांत गांवों और जिलों में पलायन जैसी चुनौतियों से निपटने में भी लैंड पोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों ओर के देशों की जनता के बीच सरल आवागमन के कारण परस्पर विश्वास बढ़ा है और संस्कृति का आदान-प्रदान भी बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल भू-सीमा वाले देश में सीमा प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।

श्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने हेतु चतुष्कोणीय रणनीति पर कार्य कर रहा है। इस स्मार्ट बॉर्डर विजन में लैंड पोर्ट अथॉरिटी की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (LPMS) में सभी हितधारकों की आवश्यकताओं तथा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। यह व्यवस्था स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना के साथ मिलकर एक अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि LPMS और स्मार्ट बॉर्डर मिलकर अधिक सुरक्षित और आधुनिक सीमा तंत्र बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे अवैध गतिविधियों पर रोक और सुरक्षित व्यवस्था का निर्माण निश्चित है।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने अपने लैंड पोर्ट्स के लिए एक आधुनिक, डिजिटल, एकीकृत और रियल-टाइम प्रबंधन प्रणाली विकसित कर सभी को एक साथ जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से लैंड पोर्ट की मूल संकल्पना को लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने पूरा कर दिया है। आगामी दिनों में हम लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को देश की स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएंगे, जिससे हमारी आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ भौतिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी की यह पहल स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना को पूर्ण रूप देने में सहायक सिद्ध होगा। यह प्रणाली कार्गो, पैसेंजर और वाहनों के प्रबंधन के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। इससे विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ेगा और सूचना का आदान-प्रदान अत्यंत सरल हो जाएगा। 90% कागजी कार्यवाही समाप्त होगी। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो तथा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान आधारित गेट संचालन प्रणाली से काफी समय की बचत होगी। ट्रकों की प्रतीक्षा समय में लगभग 40% से 60% की कमी आएगी तथा गेट प्रोसेसिंग समय में 22% से 35% की कमी होगी। इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के नागरिकों के बीच समन्वय, संवाद तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी बेहतर तरीके से हो सकेगा।

गृह मंत्री ने कहा कि छढटर के माध्यम से कउएऋअळए, मोटर वाहन प्रणाली, उइकउ, इरऋ उऋ्रह्ळ, वकऊअक और वछक्ढ एक मंच पर रियल-टाइम डेटा साझा होने से सीमा पर एजेंसियों के बीच समन्वय और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि इन सभी के बीच समन्वय और सूचना आदान-प्रदान का प्लेटफॉर्म देश के लिए बेहद सुविधाजनक सिद्ध होगा तथा विकास को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में लैंड पोर्ट्स में भी व्यापक बदलाव आया है। वर्ष 2014 में जहाँ

लैंड पोर्ट्स के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता था, वह आज बढ़कर 83,000 करोड़ रुपए हो गया है, यानि इसमें 16 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 15 लैंड पोर्ट कार्यरत हैं और आने वाले 3 वर्षों में 11 अतिरिक्त लैंड पोर्ट भी संचालन में आ जाएंगे।

श्री अमित शाह ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लैंड पोर्ट्स को लेकर जो संकल्पना रखी है, उसे हम समयबद्ध तरीके से अवश्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी की यह पहल जब स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना से जुड़ेगी, तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी हमारी आर्थिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा दोनों का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाएगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 9 जून 2026 देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन के तौर पर गिना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री के तौर पर श्री नरेन्द्र मोदी जी के सतत शासन के 12 साल पूरे होने का अवसर है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता सत्ता में टिके रहने में ही ज्यादातर समय बिता देते हैं, लेकिन मोदी जी ने बीते 12 साल की सत्ता को साधना के रूप में स्वीकार करते हुए संपूर्ण देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश सेवा को ही जीवन का अर्थ बनाकर देश को आगे ले जाने का संकल्प ले रखा है। निष्काम कर्मयोगी की तरह मोदी जी ने ऐसी अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिनके कारण आज भारत हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर मील का पत्थर बनकर उभरा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 4398 दिन का कार्यकाल आज पूरा करेंगे और कल श्री जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अब देश में चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सबसे अधिक समय तक देश की सेवा करने का सौभाग्य प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जन कल्याण को शासन का सूत्र बनाया।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक नया विचार रखा कि भारत का हर नागरिक ऐसा हो, जिसके पास अपना पक्का घर हो। देखते-देखते आज 4 करोड़ पक्के घर भारत के नागरिकों को मिल चुके हैं और 2 करोड़ घरों का निर्माण होने वाला है। उन्होंने कहा कि दो साल बाद भारत में एक भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास अपना पक्का घर न हो। घर के साथ गैस सिलिंडर, शौचालय, शुद्ध पेय जल, 5 लाख रुपए तक का मुफ़्त इलाज, प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 से 7 किलो मुफ़्त अनाज जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चार-चार पीढ़ियों से बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को मोदी जी ने अपने कार्यकाल के मात्र 12 वर्षों में यह बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी ने विकास के मायने बदल दिए। मोदी जी ने भारत के प्रशासनिक इतिहास में हर आयाम को छूने वाले '360 डिग्री विकास' की परिकल्पना शुरू की। भारत को पहले 'फ्रेजाइल फाइव' में गिना जाता था, जबकि मोदी जी के इन प्रयासों के कारण आज भारत सभी बड़े देशों में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बन गया है। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत स्थिरता और तेज गति के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत के लोकतंत्र में आमूलचूल बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार ऐसे नासूर बन गए थे कि लोग इनके साथ जीने की आदत डाल चुके थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मूलभूत परिवर्तन किया। उन्होंने परिवार की राजनीति, जाति की राजनीति और भ्रष्टाचार से कमाए धन के प्रभाव वाली राजनीति की जगह परफॉर्मेंस की राजनीति को स्थापित किया। इसके परिणामस्वरूप अनेक राज्यों में बार-बार चुनी जाने वाली सरकारें आईं, स्थिरता आई, स्थायी नीतियाँ बनीं और नीतियों का क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग सरल हो गया। इस देश के राजनीतिक इतिहास में अगर किसी को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस करने का श्रेय दिया जाए, तो वह श्रेय मोदी जी को जाता है। गृह मंत्री ने कहा कि महिला विकास की बात करने की जगह मोदी जी महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़े। सेना, पुलिस, विज्ञान, अनुसंधान, उद्यमिता, ड्रोन, खेल, स्टार्टअप, अंतरिक्ष - हर क्षेत्र में पहले इस देश की बेटियों को आगे बढ़ाने में समाज में झिझक थी। उन्होंने कहा कि आज कठिन से कठिन बॉर्डर इलाकों में तैनात बीएसएफ की सीमा प्रहरियों में बेटियाँ बराबर की संख्या में दिखती हैं, तो मन गद्गद हो जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने नागरिकों से संवाद की संकल्पना को भी बदला। आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों की रचना कर उन्होंने समावेशी विकास की परिकल्पना को जमीन पर उतारा। विकास की दौड़ में पीछे रह गए जिलों को 30 से अधिक पैरामीटर्स पर विकास का लक्ष्य और पर्याप्त संसाधन देकर उन्हें देश के सबसे विकसित जिलों के बराबर लाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि कुछ आकांक्षी जिले अब कई पैरामीटर्स में देश के टॉप पाँच जिलों के बराबर पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास की यह कल्पना अब प्रशासनिक प्रेरणा, लोगों की आकांक्षाओं को जगाने और पुरुषार्थ से जुड़कर आगे बढ़ रही है, जबकि पहले यह माना जाता कि था कि जो जिस जिले से मंत्री या सांसद बनेगा, वही अपने जिले का विकास करेगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि बीते 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 81 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन मिल रहा है। 58 करोड़ नए जनधन बैंक खाते खुले हैं। 44 करोड़ से अधिक लोगों के पास 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड हैं। 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुँचा है। 13 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सहायता मिली है। 12 करोड़ 76 लाख घरों में शौचालय बने हैं। 10 करोड़ 55 लाख घरों में गैस कनेक्शन पहुँचा है। 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का आवास मिला है। 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण गरीब महिलाएँ लखपति दीदी बन चुकी हैं और 93 लाख स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं। आज भारत डिजिटल लेन-देन में दुनिया में नंबर एक, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर दो और स्टार्टअप इकोसिस्टम में नंबर तीन पर है। उन्होंने कहा कि चाहे कोविड की महामारी हो या वैश्विक युद्धों के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट, हमने भारत को संभाला और आगे बढ़ाया। लगातार 12 वर्ष के जीडीपी के आँकड़े साक्षी हैं कि कठिनाइयाँ आईं, लेकिन दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व के जरिए हमने चुनौतियों का सामना किया। भारत के कोविड प्रबंधन को विकसित देशों ने भी दुनिया में आई महामारियों से निपटने के इतिहास में एक रिकॉर्ड के रूप में स्वीकारा है।

ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारी के बाद गेंदबाजों का कहर, रोमांचक मैच में भारत ने श्रीलंका को रौंदा

(जीएनएस)।

श्रीलंका में खेली जा रही त्रिकोणीय वनडे सीरीज के मुकाबले में भारत ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए। टीम की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि कप्तान तिलक वर्मा ने भी जिम्मेदारी भरी अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में खेलते हुए श्रीलंकाई टीम स्कोर के करीब जाकर मैच हार गई।

भारत ए की शुरूआत हालांकि उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और 12 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान उन्होंने तीन चौके लगाए।

प्रियांश आर्या और ऋतुराज ने संभाली पारी

शुरूआती झटकों के बाद प्रियांश आर्या और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी को संभालने की कोशिश की। प्रियांश ने 32 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें चार चौके और एक छक्का शामिल था। हालांकि वह रन आउट होकर पवेलियन लौट गए।

इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने एक छोर संभाले रखा और बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 114 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन बनाए। उनकी पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। मुश्किल परिस्थितियों में खेली गई यह पारी भारत ए के लिए बेहद अहम साबित हुई।

कप्तान तिलक वर्मा ने निभाई जिम्मेदारी

ऋतुराज का साथ कप्तान तिलक वर्मा ने बखूबी निभाया। तिलक ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए 97 गेंदों में 60 रन बनाए। उन्होंने दो चौके और एक छक्का लगाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई महत्वपूर्ण साझेदारी ने भारत ए को बड़े स्कोर की ओर बढ़ाया।

निचले क्रम ने किया जोरदार फिनिश

अंतिम ओवरों में आयुष बडोनी और सूर्यांश शेडगे ने तेजी से रन जुटाए। बडोनी ने 18 गेंदों पर 24 रन बनाए, जबकि सूर्यांश शेडगे ने सिर्फ 14 गेंदों में नाबाद 26 रन ठोक दिए। उनकी पारी में एक चौका और दो छक्के शामिल रहे। अंत में अनुकूल रॉय 2 गेंदों में 1 रन बनाकर नाबाद लौटे।

भारत ए को अतिरिक्त रनों के रूप में 17 रन मिले, जिसमें 16 वाइड शामिल थे। श्रीलंका ए के गेंदबाजों ने दबाव बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने नियमित अंतराल पर साझेदारियां बनाकर स्कोर को 277 तक पहुंचा दिया।

लक्ष्य के करीब जाकर श्रीलंका की हार

278 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ए की टीम ने शानदार लड़ाई दिखाई, लेकिन जीत से महज 8 रन दूर रह गई। टीम 48.5 ओवर में 269 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। सलामी बल्लेबाज निरोशन डिकवेला (47) और अविष्का फर्नांडो (45) ने तेज शुरूआत दी, जबकि सदीरा समरविक्रमा ने 46 रन बनाकर पारी को आगे बढ़ाया। कप्तान सहान अराचिगे ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 72 गेंदों में 74 रन बनाए।

क्या है 12 रिजर्व सीटों का विवाद जिसके लिए पीओके में हो रही हिंसा? क्या है पाक के संविधान में?

(जीएनएस)।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में सरकार और एक जमीनी आंदोलन के बीच टकराव अब इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बन गया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि इस मुद्दे पर अब ब्रिटिश संसद में भी चर्चा हो रही है। हालिया हिंसा में कम से कम 7 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। ये हालात हाल के सालों में PoK के सबसे गंभीर राजनीतिक और सामाजिक टकरावों में से एक माना जा रहा है। जिसमें आम जनता और पाकिस्तान की पुलिस (जिसको आर्मी का पूरा सपोर्ट है) आमने-सामने हैं। इस पूरे आंदोलन के केंद्र में जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) है, जो शुरूआत में आर्थिक मुद्दों को लेकर बने एक जनआंदोलन के रूप में सामने आई थी, लेकिन समय के साथ इसकी मांगें संवैधानिक सुधारों तक पहुंच गईं।

JAAC का गठन 2023 में बढ़ती महंगाई, बिजली की ऊंची कीमतों और आटे की लागत को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुआ था। शुरूआत में संगठन का फोकस आर्थिक राहत और बुनियादी सुविधाओं पर था, लेकिन बाद में इसने राजनीतिक और संवैधानिक सुधारों की मांग भी उठानी शुरू कर दी। इसी कारण यह आंदोलन अब केवल महंगाई विरोधी अभियान नहीं रह गया, बल्कि ढङ्खड की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाने लगा है।

पिछले कई हफ्तों से तनाव बढ़ रहा था क्योंकि खअअउ ने 9 जून को बड़े प्रदर्शन का आ'ान किया था। यह प्रदर्शन PoK विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों के खिलाफ था। ये सीटें उन कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो 1947 के विभाजन के बाद भारतीय जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान में जाकर बस गए थे। खअअउ नेताओं का आरोप है कि इन सीटों के जरिए पाकिस्तान की बड़ी राजनीतिक पार्टियां मुजफ्फराबाद की राजनीति और सरकार गठन पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव डालती हैं। संगठन का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों की राजनीतिक ताकत कमजोर होती है।

PoK की विधानसभा में कुल 45 सदस्य होते हैं। इनमें से 33 सीटें PoK के भीतर के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनी जाती हैं। 12 सीटें उन "जम्मू-कश्मीर शरणार्थियों" के लिए आरक्षित हैं, जो 1947 या बाद के संघर्षों के दौरान भारतीय जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान चले गए और अब पाकिस्तान के अलग-अलग प्रांतों में रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 12 सीटों के मतदाता PoK में नहीं रहते, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और अन्य इलाकों में बसे हुए हैं। इन 12 सीटों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। मतदान पाकिस्तान के मुख्य भूभाग में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थी करते हैं।

'31 स्टार्टअप्स हजारों नए रोजगार पैदा करेंगे', मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कही बड़ी बात

(जीएनएस)।

वर्तमान समय में पंजाब नवीन विचारों, विशिष्ट सोच और उद्यमी युवाओं द्वारा लीक से हटकर पहलकदमियां करने के कारण विकास की नई कहानी रच रहा है, जिसकी वजह से राज्य देश भर में सबसे पसंदीदा स्टार्टअप स्थल के रूप में उभर रहा है जहां युवा अपने विचारों को व्यवसाय और रोजगार के अवसरों में बदल रहे हैं।

इस सोच की पैरवी करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 31 स्टार्टअप्स और उनके संस्थापकों को 1.07 करोड़ रुपए की सीड ग्रांट वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सफल उद्यमियों की अगली पीढ़ी न सिर्फ पंजाब से आए बल्कि पंजाब में अपनी कंपनियां भी स्थापित करे, जिससे राज्य के अंदर ही नौकरियों और कमाई के अवसर पैदा हों।

स्टार्टअप को पंजाब के भविष्य के आर्थिक विकास का मुख्य स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है कि किसी भी शानदार उद्यम को वित्तीय सहायता की कमी के कारण छोड़ा न जाए।

'पंजाब स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026'

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'पंजाब स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026' के तहत सीड ग्रांट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसमें 7 स्टार्टअप्स को 5-5 लाख रुपये और 24 स्टार्टअप्स को 3-3 लाख रुपए की ग्रांट मिल रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये उद्यम रोजगार के हजारों अवसर पैदा करेंगे और युवाओं में नौकरियों की तलाश में विदेश जाने के रुझान को कम करने में मदद करेंगे।

भारत का स्टार्टअप हब बनने के रास्ते पर पंजाब

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मुफ्त बिजली, किसानों को दिन में बिजली सप्लाई और कई अन्य सुधारों जैसी पहलकदमियों से यह पता चलता है कि कैसे नए विचार लोगों को सीधा लाभ पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमिता और नवाचार में मिल रहे भरपूर समर्थन के साथ पंजाब, भारत का स्टार्टअप हब बनने के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है।

'पंजाब के उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक दिन'

स्टार्टअप्स को सीड ग्रांट वितरित करने संबंधी समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री

भगवंत सिंह मान ने कहा, "आज पंजाब के उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, खासकर हमारे युवा उद्यमियों के लिए जो नए विचारों के साथ अपना कारोबारी सफर शुरू कर रहे हैं। 31 स्टार्टअप्स को 1.07 करोड़ रुपए की सीड ग्रांट दी जा रही है। 7 स्टार्टअप्स को 5-5 लाख रुपए की ग्रांट मिल रही है, जबकि 24 स्टार्टअप्स को 3-3 लाख रुपए की ग्रांट मिल रही है। ये युवा उद्यमी अपने विचारों के माध्यम से सपनों को साकार कर रहे हैं और वे इस सहयोग के हकदार हैं।"

झाड़ू ने राजनीतिक व्यवस्था को साफ किया: सीएम भगवंत मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "आम आदमी पार्टी (आप) खुद एक ऐसे विचार से पैदा हुई थी जब देश में परिवारवाद की राजनीति का दबदबा था और आम आदमी को अनदेखा कर दिया गया था। कई पहलुओं से 'आप' एक स्टार्टअप भी थी जिसने झाड़ू के अपने प्रतीक के साथ राजनीतिक व्यवस्था को साफ किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के लोगों ने 7 पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवारों को बाहर का रास्ता दिखाया और ईमानदार सरकार को मौका दिया। उस फैसले ने पंजाब को बदल दिया है और इसे देश का एक अग्रणी राज्य बना दिया है।"

'हमारे युवा पंजाब के भविष्य को नया रूप दे रहे'

वना को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाबी अपनी मेहनत, जज्बे और उद्यम के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उसी भावना से प्रेरित होकर हमारे युवा नए उद्यम शुरू कर रहे हैं और नए अवसर पैदा कर रहे हैं। वे सिर्फ कारोबार नहीं चला रहे, वे पंजाब के भविष्य को नया रूप दे रहे हैं।"

'कारोबार स्थापित करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं'

पंजाबी मूल के सफल उद्यमियों के उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "भारत और दुनिया भर में बहुत सी सफल कंपनियां पंजाबियों द्वारा स्थापित या सह-स्थापित की गई हैं। जोमैटो, ओला और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां इसकी उदाहरण हैं कि कैसे पंजाबियों ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। पंजाब हमेशा उद्यमियों की धरती रहा है। पंजाबी जहां भी जाते हैं, वे कारोबार स्थापित करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। हमारा लक्ष्य है कि सफल संस्थापकों की अगली पीढ़ी न सिर्फ पंजाब से आए बल्कि पंजाब में अपनी कंपनियां भी स्थापित करे।"

इनोवेशन इको-सिस्टम (नवीनतम प्रणाली) की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "सीड मनी (स्टार्टअप के लिए सहायता राशि) प्रदान करने का उद्देश्य स्टार्टअप्स पर आने वाले शुरूआती बोझ को कम करना और उन्हें अपने विचारों को हकीकत में बदलने तथा आगे बढ़ने का भरोसा देना है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नवाचार के केंद्र बनना चाहिए जहां विचार क्लासरूम से परे उत्पाद, सेवाएं, कंपनियां और समाधान की नींव बनते हैं।"

'इको-सिस्टम को सही ढंग से डिजाइन किया जाता है'

अपने विदेशी दौरों को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दक्षिण कोरिया के पैंगयो टेक्नो वैली और नीदरलैंड्स के वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर में उन्होंने देखा कि कैसे एक योजनाबद्ध इनोवेशन इको-सिस्टम पूरे क्षेत्र को बदल सकता है।

इस मॉडल से पता लगता है कि जब इको-सिस्टम को सही ढंग से डिजाइन किया जाता है तो विचार विश्व स्तरीय कंपनियों की नींव बन सकते हैं। इसी तरह नीदरलैंड्स में वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर के अपने दौरे के दौरान मैंने देखा कि कैसे इनोवेशन नई तकनीकों की टेस्टिंग, लागूकरण और व्यावसायीकरण के माध्यम से खेतीबाड़ी और बागबानी को बदल सकती है।"

हमारे किसान हमेशा प्रगतिशील रहे हैं- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

पंजाब की कृषि क्षमता के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब में भविष्य का विकास उच्च-मूल्य वाली खेतीबाड़ी, एग्री-टेक, फूड प्रोसेसिंग, सुरक्षित खेती, कोल्ड चेन और एग्री-लॉजिस्टिक्स के माध्यम से होना चाहिए। हमारे किसान हमेशा प्रगतिशील रहे हैं और पंजाब सरकार उन्हें आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार और नए कारोबारी मॉडलों तक पहुंच प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।"

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

एनडीआरएफ की तर्ज पर यूपी में बनेगा स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ग्रुप, हर तहसील तक पहुंचेगी फायर सर्विस, जानें योगी सरकार का पूरा प्लान

(जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आपदा और दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ की तर्ज पर स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ग्रुप (एसआरजी) बनाया जाएगा। 240 कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर तहसील तक फायर सर्विस पहुंचाने, हाईराइज भवनों के लिए आधुनिक अग्निसुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और फायर सेवाओं के विस्तार के निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश में आपदा और विशेष आपात परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ग्रुप (एसआरजी) का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहले चरण में प्रदेश के 10 जिलों में एसआरजी की स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए 240 कर्मियों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) समेत अन्य विशेषज्ञ संस्थानों में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सोमवार को अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से शहरी, औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन एवं आपात सेवा व्यवस्था को समय की जरूरतों के अनुरूप और मजबूत बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग अब केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन, संपत्ति, उद्योगों और निवेश की सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआरजी भवन ध्वस्त होने, बाढ़, रासायनिक दुर्घटनाओं, ऊंचाई पर फंसे लोगों के रेस्क्यू और संकरे स्थानों में बचाव

जैसे जटिल अभियानों में आधुनिक उपकरणों और विशेष प्रशिक्षण के साथ त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम होगी।

296 तहसीलों में संचालित हैं 326 अग्निशमन केंद्र

बैठक में डीजी फायर सर्विस ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 स्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा 47 नए केंद्रों की डीपीआर तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने शेष तहसीलों में भी अग्निशमन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

हाईराइज भवनों के लिए खरीदे जाएंगे आधुनिक उपकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में तेजी से बढ़ रही बहुमंजिला इमारतों ने अग्निसुरक्षा की नई चुनौतियां पैदा की हैं। इनसे निपटने के लिए आधुनिक संसाधनों और विशेष व्यवस्थाओं की जरूरत है। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2026-27 में 102 मीटर क्षमता के 10, 90 मीटर क्षमता के तीन और 72 मीटर क्षमता के सात हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने की योजना है। इसके अलावा 100 मंजिल तक प्रभावी अग्निशमन क्षमता वाले आधुनिक तकनीक से लैस 14 विशेष फायर फाइटिंग वाहनों की खरीद भी प्रस्तावित है।

नौ वर्षों में दोगुनी से अधिक बढ़ी विभाग की क्षमता

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 के बाद से अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश में अग्निशमन केंद्रों की संख्या 140 से बढ़कर 260 हो गई है तथा 114 नए केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी अवधि में फायर वाहनों की संख्या 750 से बढ़कर 1660 हो गई है, जबकि 400 अतिरिक्त वाहनों की खरीद प्रक्रिया जारी है। डायल-112 के साथ एकीकरण, ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार और नई भर्तियों से विभाग की कार्यक्षमता में भी सुधार हुआ है।

फायर ऑडिट और जनजागरूकता पर जोर

मुख्यमंत्री ने फसलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए जनजागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत बनाने पर बल दिया। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेशभर में 1.20 लाख से अधिक फायर ऑडिट किए गए। इसके अलावा 31 हजार से अधिक मॉक ड्रिल, 75 हजार से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और 16.55 लाख लोगों तक पहुंचने वाले जनजागरूकता अभियान चलाए गए। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों, होटलों, स्कूलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों में नियमित फायर ऑडिट कराने तथा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

फायर एनओसी प्रक्रिया हुई और आसान

निवेश और उद्योगों की जरूरतों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने फायर एनओसी व्यवस्था को और अधिक सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि फायर सर्विस पोर्टल को निवेश मित्र 3.0 से एकीकृत किया जा चुका है। एनओसी की वैधता अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है। 1 जनवरी से 31 मई 2026 के बीच प्राप्त 14,717 ऑनलाइन आवेदनों में से 10,670 मामलों में एनओसी जारी की गई है।

सभी ब्लॉकों में तैयार किए गए अग्निमित्र

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी ब्लॉकों में अग्निमित्र और अग्निसचेतक तैयार करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2026 में लगभग 44 हजार स्वयंसेवकों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी चरण में इनके लिए समर्पित वेब पोर्टल और मोबाइल एप विकसित किया जाएगा। साथ ही सिविल डिफेंस, होमगार्ड और पीआरडी जैसी इकाइयों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा।

जो भारत की संस्कृति, विरासत और मूल्यों का सम्मान करेगा वही यहां सम्मानपूर्वक रह सकेगा: सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत की धरती कोई धर्मशाला नहीं है। जो भारत की संस्कृति, विरासत और मूल्यों का सम्मान करेगा, वही ...और पढ़ें

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत और जीवन मूल्यों से है। इसलिए जो लोग इनका सम्मान करते हैं, वही इस देश की आत्मा से जुड़ सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की धरती कोई धर्मशाला नहीं है। जो भारत की संस्कृति, विरासत और मूल्यों का सम्मान करेगा, वही यहां सम्मानपूर्वक रह सकेगा। जो भारत की आत्मा और उसके संस्कारों को स्वीकार नहीं कर सकता, उसके लिए यहां कोई स्थान नहीं है।

सीतापुर रोड स्थित ब्रज की रसोई परिसर में आयोजित श्रीराम कथा के समापन समारोह में भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे।

रामभद्राचार्य के योगदान को बताया प्रेरणादायी

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पद्म विभूषण जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि चित्रकूट

में देश के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कर उन्होंने सेवा, समर्पण और सामाजिक उत्थान का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि इस आयु में भी रामभद्राचार्य महाराज विश्राम करने के बजाय देश-विदेश में श्रीराम कथा के माध्यम से लोकमंगल और राष्ट्रजागरण का कार्य कर रहे हैं।

'श्रीराम का नाम देश को जोड़ने वाला सूत्र'

सीएम योगी ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन किसी राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्ति का आंदोलन नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का नाम वह सूत्र रहा है, जिसने उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश को सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से एकजुट रखने का कार्य किया।

उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति भगवान राम के आदर्शों का थोड़ा-सा अंश भी अपने जीवन में आत्मसात कर ले, तो न केवल उसका जीवन बेहतर बन सकता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है।

कंस और मारीच के प्रसंगों से दिया संदेश

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पौराणिक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि इतिहास और धर्मग्रंथ हमें सज्जन शक्ति को संगठित करने तथा अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कंस और मारीच के उदाहरण देते हुए कहा कि गलत संगति और स्वार्थपूर्ण सलाह हमेशा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक साबित होती है।

यह भी पढ़ें- अखिलेश यादव का बड़ा दावा, प्रयागराज की सभी सीटों पर उम्मीदवार बदलने की भाजपा कर रही तैयारी, 2027 में 225 विधायकों के कटेंगे टिकट

'संत समाज हमेशा जोड़ने का काम करता है'

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ शक्तियां समाज को जाति, क्षेत्र, भाषा और अन्य आधारों पर विभाजित करने का प्रयास करती हैं, जबकि संत समाज सदैव लोगों को जोड़ने, सामाजिक समरसता बढ़ाने और राष्ट्र को मजबूत करने का कार्य करता है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम के आदर्श और संतों का सानिध्य व्यक्ति को जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक ऊर्जा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

यूपी में सभी 403 विधानसभा में बनेगी 80 करोड़ की लागत से सड़कें-पुलिया, 10 जून के बाद सीएम योगी शुरू करेंगे मंडलीय दौरे, हर दिन जाएंगे 2 मंडल

अब मुख्यमंत्री योगी 10 जून के बाद जब मंडलीय दौरे पर निकलेंगे तो वह दल के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे. मुख्यमंत्री एक दिन में दो-दो मंडलों का दौरा करेंगे. यूपी में सभी 403 विधानसभा में बनेगी 80 करोड़ की लागत से सड़कें-पुलिया, 10 जून के बाद सीएम योगी शुरू करेंगे मंडलीय दौरे, हर दिन जाएंगे 2 मंडल 403 विधानसभा क्षेत्रों 80 से 85 करोड़ रुपए विकास करने के लिए जिलों की कार्ययोजना मंगा ली गई है. बजट न खर्च कर पाने के कारण वापस हो जाने वाली विभागीय धनराशि को लेकर विपक्ष की आलोचना से भी बचा जा सकेगा. मुख्यमंत्री योगी ने बहुत सोच-विचार कर गांवों में सड़क और पुलिया के निर्माण की योजना तैयार की है.

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले की अगले साल होने हैं, लेकिन सूबे की योगी सरकार पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई. इसके चलते ही अब गांवों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर सरकार से अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए सूबे के 403 विधानसभा क्षेत्रों 80 से 85 करोड़ रुपए विकास करने के लिए जिलों की कार्ययोजना मंगा ली

गई है.

बताया जा रहा है कि सरकार की मंशा हर विधानसभा क्षेत्र में सड़क और पुलिया के निर्माण में 80 से 85 करोड़ रुपए खर्च करने की है. ताकि विधानसभा चुनावों के पहले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश सरकार के कराए यह कार्य लोगों को दिखाई दे. इसके अलावा हर साल बजट न खर्च कर पाने के कारण वापस हो जाने वाली विभागीय धनराशि को लेकर विपक्ष की आलोचना से भी बचा जा सकेगा.

पुलिया और सड़क का निर्माण क्यों

इस सोच के चलते ही मुख्यमंत्री योगी ने बहुत सोच-विचार कर गांवों में सड़क और पुलिया के निर्माण की योजना तैयार की है. अब मुख्यमंत्री योगी 10 जून के बाद जब मंडलीय दौरे पर निकलेंगे तो वह दल के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे. मुख्यमंत्री एक दिन में दो-दो मंडलों का दौरा करेंगे.

इस दौरान मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों से उनके द्वारा प्रस्तावित किए गए कार्यों में से उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी करेंगे. जनप्रतिनिधि जिस कार्य को अधिक महत्वपूर्ण बताएंगे वह काम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विभागों से कार्य करने का कहा जाएगा.

इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सड़क और पुलिया के निर्माण को लेकर मिले आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अफसरों को दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी का मानना है कि सड़क और पुलिया के निर्माण की मांग हर ग्रामीण करता है और इनका निर्माण होने के ग्रामीण खुश होते हैं, इस विधानसभा चुनाव के पहले हर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में यह कार्य जरूर करवाए जाएं.

पीडब्ल्यूडी के बजट से होगा निर्माण

वैसे भी सड़क और पुलिया के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी के पास धन के कमी नहीं है.पीडब्ल्यूडी को इस वर्ष विकास कार्यों के लिए 35,156 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. जिसमें से 11,718 करोड़ रुपए नए कार्यों के लिए है. शेष बजट पहले से चल रही योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है.

विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी के मुताबिक लगभग 35 हजार करोड़ रुपए से नई सड़कें व पुल-पुलियों के निर्माण कार्य इस वर्ष कराए जाएंगे. जिलों से मिली कार्ययोजना में से चिन्हित किए जाने वाले कार्यों को शुरू कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कराई जाएगी, ताकि दिसंबर तक बजट का पूरा उपयोग किया जा सके.

इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुलिया के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विभाग पूरा कराएगा. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुहैया करने के लिए तालाब के निर्माण, तालाबों की सफाई और हैंडपंप आदि ठीक करने का कार्य भी जोर-शोर से किया जाएगा.

भीषण गर्मी में भी बिजली आपूर्ति में यूपी नंबर-1, सीएम योगी बोले- किसी भी हाल में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए

(जीएनएस)।

लखनऊ, भीषण गर्मी में उत्तर प्रदेश बिजली आपूर्ति में देश का नंबर-1 राज्य बन गया है. 7 जून को 31,147 मेगावाट रिकॉर्ड डिमांड पूरी की गई. उट योगी के निर्देश पर बिजलीकर्मी दिन-रात सक्रिय हैं.

बिजली आपूर्ति में यूपी नंबर वन

प्रचंड गर्मी के बावजूद उत्तर प्रदेश बिजली आपूर्ति में देश का नंबर-1 राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतर्क निर्देशन में यूपी पावर कारपोरेशन (यूपीपीसीएल) ने 7 जून को 31,147 मेगावाट की रिकॉर्ड डिमांड पूरी की, जो देश में सबसे अधिक है.

यूपीपीसीएल के निदेशक वितरण ज्ञानेंद्र धर द्विवेदी ने बताया कि 7 जून को प्रदेश में बिजली की मांग 31,147 मेगावाट पहुंच गई, जिसे पूरी तरह पूरा किया गया. 6 जून को 31,049 मेगावाट और 5 जून को 29,130 मेगावाट डिमांड पूरी की गई. 8 जून को दोपहर 12 बजे 27,838 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई.

मेरठ में मॉडल को शादी का झांसा देकर 10 साल शोषण, 3 बार अबॉर्शन और धर्मांतरण का बनाया दबाव

दिन-रात मैदान में डटे बिजलीकर्मी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बिजली विभाग की टीमें चौबीसों घंटे सक्रिय हैं. ट्रांसफार्मर, फीडर और उपकेंद्रों की निरंतर निगरानी की जा रही है. गर्मी के मौसम में अतिरिक्त लोड को देखते हुए मेंटेनेंस कार्य तेज कर दिए गए हैं. बिजलीकर्मी दिन-रात फील्ड में रहकर खराबियों को तुरंत दूर कर रहे हैं.

निगरानी और रखरखाव पर विशेष ध्यान

विभाग ने सभी स्तरों पर सतर्कता बढ़ा दी है. संभावित खराबियों को रोकने के लिए तेजी से मेंटेनेंस किया जा रहा है. शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है.

मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश

सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गर्मी के इस मौसम में किसी भी हाल में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए. यूपीपीसीएल की टीमें इस चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा कर रही हैं.

अब CUET-UG कराएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में बीफार्मा में प्रवेश, जल्द आएगा फॉर्म

(जीएनएस)।

लखनऊः लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में संचालित बी.फार्म. पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रवेश प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. अब तक बी.फार्म. में प्रवेश डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) द्वारा आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता था, जबकि इस वर्ष से लखनऊ विश्वविद्यालय स्वयं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) के आधार पर प्रवेश प्रदान करेगा.

लखनऊ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉ. भावना मिश्रा ने बताया कि इ.ढँ१. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए CUET-UG 2026 में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा. CUET-UG का रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः उवएळ-वऋ में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार संचालित की जाएगी.

बी.फार्म. पाठ्यक्रम की 60 सीटों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारवीं (10+2) परीक्षा PCB/ PCM/ PCMB (जिसमें अंग्रेजी एक विषय हो) में उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे CUET-UG परिणाम घोषित होने के पश्चात निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें और प्रवेश संबंधी नवीनतम सूचनाओं के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें.

उल्लेखनीय है कि बी.फार्म. पाठ्यक्रम 4 साल की स्नातक डिग्री है, जो 8 सेमेस्टर में विभाजित है. साल 2021 से संचालित इस पाठ्यक्रम के 2 बैच सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो चुके हैं. वर्तमान में इसके पहले छात्र फार्मास्युटिकल उद्योग, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

लखनऊः सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में फायर सेफ्टी के काम के दौरान गिरी फॉल सीलिंग; बाल-बाल बचे 9 मरीज

(जीएनएस)।

लखनऊः लखनऊ के प्रतिष्ठित सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में उस समय अचानक अफरा-तफरी मच गई जब फाइबर की फॉल सीलिंग का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया. यह हादसा उस वक्त हुआ जब इमरजेंसी वार्ड के अंदर फायर सेफ्टी से जुड़ा कुछ जरूरी काम चल रहा था.

गनीमत यह रही कि मलबे की सीधी चपेट में कोई मरीज या उनका तीमारदार नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया. लखनऊ सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवेश चंद्र पांडेय ने बताया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

हादसे के वक्त वार्ड में भर्ती थे 9 मरीजः मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवेश चंद्र पांडेय ने कहा कि दोपहर के समय इमरजेंसी वार्ड में फायर सेफ्टी उपकरणों की नियमित जांच और मरम्मत का कार्य निर्माण एजेंसी करा रही थी. इसी मरम्मत कार्य के दौरान छत पर ऊपर लगी फाइबर की फॉल सीलिंग अचानक भरभराकर धड़ाम से नीचे आ गिरी. सीलिंग गिरने की तेज आवाज सुनते ही वार्ड में भर्ती मरीजों के तीमारदार और ड्यूटी पर तैनात अस्पताल स्टाफ बुरी तरह घबरा गए.

मरीजों को सुरक्षित वार्डों में किया गया शिफ्टः हादसे के वक्त इमरजेंसी वार्ड में कुल 9 गंभीर मरीज भर्ती थे, जिन्हें तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया. स्थिति की गंभीरता और खतरे को देखते हुए इमरजेंसी वार्ड को डॉक्टरों के निर्देश पर तुरंत खाली करा लिया गया. इसके बाद सभी मरीजों को अस्पताल के अन्य सुरक्षित वार्डों में बेड अलॉट कर इलाज के लिए भेजा गया. मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी रवि शंकर ओझा ने बताया कि फॉल सीलिंग गिरने से कुछ महंगे मेडिकल उपकरण और फर्नीचर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं.

हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंपः इस अचानक हुए हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पीडब्ल्यूडी की इंजीनियरिंग टीम को बुलाकर बाकी बची सीलिंग की तकनीकी जांच कराई गई. इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इमरजेंसी क्षेत्र को मरीजों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया.

उटर ने दिए जांच के आदेशः मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया कि सिविल अस्पताल में रखरखाव के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति होती है. लखनऊ सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवेश चंद्र पांडेय ने बताया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं. फायर सेफ्टी का काम कर रही कार्यदायी एजेंसी और अस्पताल के संबंधित अधिकारियों से इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी स्थिति का जायजा लेकर इमरजेंसी वार्ड को जल्द सुरक्षित बनाकर यहां सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

नगर आयुक्त ने नाला सफाई कार्यों का किया निरीक्षण, कहा- 'नालों की सफाई गंभीरता से की जाए'

(जीएनएस)।

लखनऊ : मंगलवार को लखनऊ नगर निगम आयुक्त गौरव कुमार ने अलग-अलग क्षेत्र में जाकर नाला सफाई का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए. नगर आयुक्त गौरव कुमार ने जोन-3 क्षेत्र के विभिन्न नालों का निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ चीफ इंजीनियर (सिविल) महेश वर्मा, अधिशासी अभियंता जोन-3 नजमी मुजफ्फर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे. निरीक्षण की शुरूआत टेढ़ी पुलिया चौराहे से इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे के मध्य स्थित सर्विस रोड के किनारे चल रहे नाला सफाई कार्य से हुई. नगर आयुक्त ने बकेट मशीन द्वारा की जा रही सफाई व्यवस्था को देखा और कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए.

नगर आयुक्त ने छुइयापुरवा चौराहे से अलीशा नगर चौराहे तक स्थित नाले का निरीक्षण किया. उन्होंने नाले की सफाई को और प्रभावी बनाने के लिए पुनः सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह सुचारु बनी रहे.

लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस के निकट रेलवे पुलिया से बिठौली चौराहे तक स्थित नाले का निरीक्षण करते हुए नगर आयुक्त ने कुछ स्थानों पर फ्लोटिंग मटेरियल (तैरने वाली सामग्री) पाए जाने पर उसे तत्काल हटाने तथा नाले की दोबारा सफाई कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या न हो, इसके लिए सभी नालों की सफाई पूरी गंभीरता से की जाए.

अधिकारियों ने नाला सफाई कार्यों का किया निरीक्षण

"कवरिंग हटाकर अंदर तक अच्छी तरह सफाई सुनिश्चित की जाए" : नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नालों की कवरिंग हटाकर अंदर तक अच्छी तरह सफाई सुनिश्चित की जाए तथा सफाई के बाद कवरिंग को व्यवस्थित ढंग से पुनः लगाया जाए. उन्होंने नाला सफाई के दौरान निकलने वाली सिल्ट को समयबद्ध तरीके से हटाने और किसी भी स्थान पर उसे जमा न होने देने के निर्देश भी दिए.

"अभियंता कार्यों की निगरानी करें" : नगर आयुक्त ने कहा कि नाला सफाई कार्यों में लगे सभी कर्मियों को आवश्यक सेफ्टी गियर्स उपलब्ध कराए जाएं तथा अभियंता नियमित रूप से कार्यों की निगरानी करें, जिससे सफाई अभियान पूरी गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ संचालित हो सके.

निरीक्षण के बाद विकास कार्यों की समीक्षा की : नाला सफाई कार्यों के निरीक्षण के बाद नगर आयुक्त ने कश्मीरी मोहल्ला स्कूल का भी निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने विद्यालय में चल रहे नवीनीकरण एवं विकास कार्यों की समीक्षा की. चीफ इंजीनियर (सिविल) महेश वर्मा एवं पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान की उपस्थिति में नए क्लासरूम निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया. नगर आयुक्त ने गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए.

तीन तलाक व एसिड पीड़िताओं के आंसू पोछेगी योगी सरकार, घर और इलाज की उठाएगी जिम्मेदारी

(जीएनएस)।

लखनऊ , योगी सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सशक्तीकरण को लेकर लगातार नए कदम उठा रही है। इसी क्रम में योगी सरकार ने तीन तलाक तथा एसिड अटैक जैसी गंभीर सामाजिक त्रासदियों से प्रभावित महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार इन पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही निराश्रित महिलाओं को भी इन सभी योजनाओं का लाभ देने की तैयारी शुरू कर दी गयी है।

कई विभागों से समन्वय स्थापित कर एकत्रित किया जा रहा डाटा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग ने विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही महिला कल्याण विभाग तीन तलाक एवं एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के साथ निराश्रित महिलाओं का विस्तृत डाटा एकत्रित किया जा रहा है, ताकि पात्र महिलाओं को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा सके। शासन स्तर पर इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और शासनादेश (जीओ) तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। महिला कल्याण विभाग द्वारा पीड़ित महिलाओं का सत्यापित विवरण एकत्रित किया जा रहा है। इसके आधार पर लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

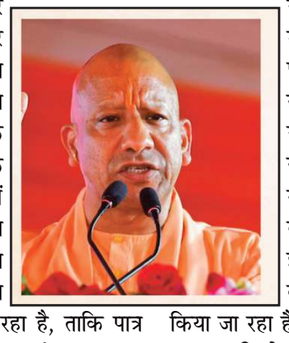

योगी सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी पात्र महिला को केवल जानकारी के अभाव या प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित न रहना पड़े। इसके लिए विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिए थे निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि जिन महिलाओं को तीन तलाक या एसिड अटैक जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और जिनके पास स्थायी आवास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही इन महिलाओं और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़कर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ दिया जाए। मालूम हो कि एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को लंबे समय तक इलाज, सर्जरी और पुनर्वास की आवश्यकता होती है। वहीं, तीन तलाक से प्रभावित कई महिलाएं आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना करती हैं। ऐसे में आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों उपलब्ध कराकर योगी सरकार उनके जीवन को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

यूपी में चुनाव से पहले नंद गोपाल गुप्ता नंदी को लगा तगड़ा झटका, सीएम योगी ने वापस ली ये जिम्मेदारी

यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यूपीडी से जुड़े से सभी कार्य अब अवस्थापना विकास अनुभाग को सौंपे जा रहे हैं. ये विभाग सीएम योगी आदित्याथ के अधीन है.

(जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बड़ा झटका लगा है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने नंदी के पास से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा विभाग ले लिया है. सीएम योगी अब खुद इस विभाग का कामकाज देखेंगे.

यूपी सरकार ने प्रदेश में एक्सप्रेसवे और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को गति देने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब एक्सप्रेस वे विभाग को अवस्थापना विभाग में शामिल किया गया है. ये विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है. सरकार का कहना है कि इससे बेहतर तालमेल और कामकाज में तेजी आएगी.

सीएम योगी खुद संभालेंगे यूपीडा विभाग

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यूपीडी से जुड़े से सभी कार्य अब अवस्थापना विकास अनुभाग को सौंपे जा रहे हैं. कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के पास पहले औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई (प्रवासी भारतीय) और यूपीडा जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे.

इस विभागीय फेरबदल में यूपीडा का कार्यभार उनसे लेकर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया गया है. नंदी के पास अब वर्तमान में औद्योगिक विकास विभाग, निर्यात प्रोत्साहन विभाग, एनआरआई (प्रवासी भारतीय) विभाग बचा है. ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि अब गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन होगी.

अखिलेश यादव ने कसा तंज

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्री नंदी से यूपीडा विभाग लिए जाने पर बीजेपी पर तंज कसा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कि जब भ्रष्टाचार और आपसी लेनदेन का टारगेट पूरा हो गया तो उन्हें हटा दिया गया. अखिलेश ने लिखा- 'अभी हाफ हुए हैं, विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा तो साफ हो जाएंगे. जब सारे 'घटिया एक्सप्रेसवे' बन गये और भ्रष्टाचार का आपसी लेनदेन का टारगेट पूरा हो गया तब हटाया तो क्या हटाया?'

यूपी में हिंदू से मुस्लिम बनवाने वालों पर सीएम योगी सख्त, जानिए ऐसे लोगों के लिए क्या बोले

(जीएनएस)।

सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में ने लड़के और लड़कियों को हिन्दू से मुस्लिम धर्मांतरण और भूमि अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर चिंता जताते हुए कहा कि समाज को नकारात्मक ताकतों के खिलाफ जागरूक और सतर्क रहना होगा. उन्होंने रामायण के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए जनजागरूकता पर जोर दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है. समाज की सक्रिय भागीदारी को भी उन्होंने जरूरी बताया.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदू से मुस्लिम बनवाने (धर्मांतरण) वाले और भूमि अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर एक बार फिर सख्त रुख दिखाया है. लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि समाज को ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो सामाजिक संतुलन और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं.

मुख्यमंत्री ने रामायण के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय समाज के सामने आने वाली कई चुनौतियों के समाधान हमारे सांस्कृतिक ग्रंथों और परंपराओं में मौजूद हैं. उन्होंने माता सीता के अपहरण और भगवान राम के संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने वाला संदेश भी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब रावण ने माता जानकी का अपहरण किया था, तब भगवान राम ने उनकी खोज और सम्मान की रक्षा के लिए उत्तर से दक्षिण तक समाज को एकजुट किया था. उनके मुताबिक यह प्रसंग केवल इतिहास या आस्था का विषय नहीं है, बल्कि समाज को संगठित रहने और गलत प्रवृत्तियों के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा भी देता है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा भारतीय संस्कृति के केंद्र में रही है. ऐसे में किसी भी प्रकार के छल, दबाव या प्रलोभन के जरिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और पहचान को प्रभावित करने की कोशिश को गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

धर्मांतरण पर कानून और जागरूकता दोनों जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाया था. उनका कहना था कि कानून अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल कानून बना देने से समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं होता. उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज में व्यापक जनजागरूकता की आवश्यकता है. लोगों को अपने अधिकारों, कानूनी प्रावधानों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए. यदि समाज सजग रहेगा तो किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सकता है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है. इसलिए केवल सरकार नहीं, बल्कि समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी.

अदालतों की टिप्पणियों का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर वर्षों पहले भी चिंता जताई जा चुकी है. उन्होंने कहा कि विभिन्न न्यायिक टिप्पणियों और सामाजिक बहसों में इस विषय पर चर्चा होती रही है, लेकिन लंबे समय तक इसे गंभीरता से नहीं लिया गया. उनका कहना था कि जब किसी मुद्दे के सामाजिक प्रभाव दूरगामी हों, तो उस पर समय रहते संवाद और जागरूकता आवश्यक हो जाती है. इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून और जनजागरूकता दोनों पर समान रूप से ध्यान देने का प्रयास किया है.

नकारात्मक ताकतें हर दौर में आती हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास गवाह है कि हर कालखंड में ऐसी ताकतें सामने आती रही हैं, जो समाज में भ्रम, विभाजन या असंतुलन पैदा करने का प्रयास करती हैं. उन्होंने कहा कि चुनौती यह नहीं है कि ऐसी प्रवृत्तियां मौजूद हैं, बल्कि यह है कि समाज उनके प्रति कितना जागरूक है. यदि समाज संगठित और सजग रहेगा तो किसी भी नकारात्मक गतिविधि को सफल होने का अवसर नहीं मिलेगा. मुख्यमंत्री ने लोगों से सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि परिवार और समाज दोनों स्तर पर संवाद और जागरूकता जरूरी है.

भूमि अतिक्रमण के मुद्दे पर भी बोले

धर्मांतरण के साथ-साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि अतिक्रमण और अवैध कब्जों के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और धार्मिक महत्व की जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या अतिक्रमण को स्वीकार नहीं किया जा सकता. राज्य सरकार इस दिशा में लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि से जुड़े विवाद केवल कानूनी विषय नहीं होते, बल्कि उनका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी होता है. इसलिए ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और सतर्कता दोनों आवश्यक हैं.

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की पहचान उसकी संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत से है. यदि समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा तो किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना अधिक मजबूती से कर सकेगा. उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से अपील की कि वे भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के बारे में पढ़ें और समझें. उनका कहना था कि जागरूक नागरिक ही मजबूत समाज का निर्माण करते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय सूचना और तकनीक का युग है. ऐसे में सही और गलत जानकारी के बीच अंतर समझना भी उतना ही जरूरी हो गया है. समाज को अफवाहों से बचते हुए तथ्यों और कानून के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए.

यूपी में जमीनों की खरीद फरोख्त में होगी और आसानी, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

सीएम योगी ने स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग को तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए. पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, अक जियो-टैगिंग और मानकीकृत मूल्यांकन में तेजी लाने के निर्देश हैं.

(जीएनएस)।

लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि रजिस्ट्री कार्यालयों को आधुनिक तकनीक, पारदर्शिता और बेहतर जनसुविधा के माध्यम से आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाए. उन्होंने उप-निबंधक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016-17 में विभाग की आय 11,613.84 करोड़ रुपये थी, जो 2025-26 में बढ़कर 32,598.49 करोड़ रुपये हो गई है. पंजीकृत लेखपत्रों की संख्या भी 28.25 लाख से बढ़कर 49.34 लाख से अधिक हो गई है. उन्होंने इस प्रगति को सराहते हुए राजस्व वृद्धि के साथ सेवा गुणवत्ता और नागरिक संतुष्टि को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए.

पेपरलेस रजिस्ट्रेशन और एआई पर जोर

सीएम योगी ने पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, अभिलेखों के डिजिटाइजेशन, जियो-टैगिंग, आधार प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक व आईरिस आधारित सत्यापन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित प्रणाली को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन सुधारों से पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद कम होंगे और स्टाम्प शुल्क चोरी पर अंकुश लगेगा.

मानकीकृत मूल्यांकन व्यवस्था से रुकेगी चोरी

मुख्यमंत्री ने संपत्तियों के मूल्यांकन में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के लिए मानकीकृत मूल्यांकन व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इससे बाजार आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित होगा और विवादों में कमी आएगी.

निवेश के अनुकूल बनाएं कानून

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से निवेश का केंद्र बन रहा है. इसलिए कॉरपोरेट पुनर्गठन, विलय, विभाजन, एलएलपी, शेयरधारिता परिवर्तन और रेरा से जुड़े प्रावधानों को समयानुकूल और व्यावहारिक बनाने की जरूरत है. उन्होंने विभिन्न राज्यों की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का अध्ययन कर ऐसा विधिक ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मजबूत हो और निवेशकों का विश्वास बढ़े.

नागरिक सुविधाएं होंगी बेहतर- योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय आमजन के प्रत्यक्ष संपर्क वाले कार्यालय हैं. यहां हेल्प डेस्क, टोकन सिस्टम, आधुनिक प्रतीक्षालय, महिला एवं शिशु कक्ष जैसी सुविधाएं विकसित की जाएं ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो. बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभाग की प्रगति, डिजिटल सुधारों और भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया.

सरस्वती शिशु मंदिर में समर कैंप संपन्न:9 दिवसीय शिविर में बच्चों ने सीखा कला और नैतिक मूल्य

(जीएनएस)।

लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित टिकैतराय तालाब के पास सरस्वती शिशु मंदिर में 9 दिवसीय समर कैंप का समापन हो गया। यह शिविर सरस्वती शिशु मंदिर और आत्ममंथन भारत ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिला।

नौ दिनों तक चले इस शिविर में बच्चों को रचनात्मक, बौद्धिक और शारीरिक विकास से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें आर्ट, क्राफ्ट, संगीत, खेलकूद और व्यक्तित्व विकास जैसे सत्र शामिल थे, जिनमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें सही दिशा देना था।

ऐसी शिक्षा वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक

इस मौके पर प्रधानाचार्या कल्पना सिंह ने बताया कि समर कैंप की एक विशेषता यह रही कि आधुनिक गतिविधियों के साथ बच्चों को आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से भी जोड़ा गया। आत्ममंथन भारत ट्रस्ट द्वारा आयोजित विशेष सत्रों में बच्चों को आत्मचिंतन, अनुशासन, संस्कार और सकारात्मक सोच का महत्व समझाया गया।

आयोजकों ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसी शिक्षा वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है।

यह कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास को यादगार बनाया

समापन समारोह में बच्चों ने शिविर के दौरान सीखे गए कला और कौशल का प्रदर्शन किया। उनकी रंग-बिरंगी कलाकृतियों, संगीत प्रस्तुतियों और रचनात्मक गतिविधियों ने अभिभावकों और अतिथियों को प्रभावित किया। बच्चों के आत्मविश्वास और उत्साह ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया।

इस अवसर पर आत्ममंथन भारत ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवेन्द्र प्रताप ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रमाण पत्र पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी।

लखनऊ में 13 लाख से अधिक के नकली नोट बरामद, 500 और 100 रुपए के जाली नोट के साथ तीन गिरफ्तार

घैला पुल के पहले दाहिने तरफ खाली पड़े मैदान में तीनों अज्ञात व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने पकड़ लिया.

(जीएनएस)।

लखनऊ : मडियांव थाना पुलिस ने नकली करेंसी बदलने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 13.95 लाख रुपए के 500 और 100 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं. पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है.

डीसीपी नार्थ गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया, थाना मड़ियांव पुलिस को सोमवार को सूचना मिली थी की थानाक्षेत्र में कुछ संदिग्ध लोग असली नोटों के बदले बड़ी संख्या में नकली नोटों का आदान प्रदान करने वाले हैं.

पुलिस टीम सक्रिय होकर गैंग का पता लगा रही थी. रात को सूचना मिली की घैला पुल के पहले दाहिने तरफ खाली पड़े मैदान में एक टीन शेड के पास तीन लड़के मौजूद हैं, जिनके पास नकली करेंसी के नोट हैं और किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं.

सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से नकली करेंसी के 500 रुपए के 1402 नोट (14 गड्डी), 100 रुपये के 6946 नोट (70 गड्डी) कुल 13,95,600 रुपये बरामद किए गए.

पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम आलोक सिंह (21) पुत्र स्व. देवेन्द्र सिंह निवासी गम्भीरवन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, सोनू गौंड उर्फ गोलू पुत्र बेचू गौंड (25) निवासी ग्राम रामपुर मुबारक पट्टी बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, बृजेश विश्वकर्मा (35) पुत्र स्व. बालचन्द्र विश्वकर्मा निवासी सारगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बताया.

पूछताछ में तीनों ने बताया कि आजमगढ़ निवासी गैंग का सरगना मंजीत और उसका साथी संतोष अभी फरार हैं. मंजीत ने ही नकली नोटों की खेप लखनऊ में एक व्यक्ति को देने

खिड़कियों के रास्ते ट्रेन में घुसने को मजबूर अभ्यर्थी, उमड़ा जनसैलाब

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन जहां एक तरफ प्रशासन 30 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरों, बायोमेट्रिक सत्यापन और पेपर लीक माफियाओं पर ताबड़तोड़ एफआईआर के जरिए साफ-सुथरी परीक्षा कराने का दावा कर रहा है, वहीं छात्रों को भारी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है. वहीं उन्नाव में आए आंधी-तूफान के कारण कानपुर से बालामऊ जा रही ट्रेन के मार्ग में पेड़ गिर गया, जिससे घंटों ट्रेन खड़ी रही और परीक्षा देने जा रहे सैकड़ों छात्रों के चेहरे पर मायूसी छा गई.

राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर सोमवार को परीक्षा के बाद भारी भीड़ देखने को मिली.स्टेशन पर स्थिति इस कदर अनियंत्रित हो गई कि अभ्यर्थी अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेनों की आपातकालीन खिड़कियों के रास्ते बोगी के अंदर जाते हुए दिखाई दिए. इस पूरी अफरातफरी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें छात्र एक-दूसरे को धक्का देते और खिड़की के संकरे रास्ते से ट्रेन के डिब्बे में घुस जाने की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं. इतनी बड़ी संख्या में युवाओं के एक शहर से दूसरे शहर जाने के कारण यातायात व्यवस्था पर भारी दबाव साफ देखा जा सकता है.

मेक्सिको में उग्र विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार का बड़ा दावा, ओपनिंग सेरेमनी का बताया प्लान!

(जीएनएस)।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के उद्घाटन मुकाबले से ठीक पहले मेक्सिको में सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा को लेकर तनाव बढ़ गया है। राजधानी मेक्सिको सिटी में शिक्षकों के संगठन और सामाजिक कार्यकताओं के उग्र विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबाम ने सोमवार को देश और दुनिया को आश्वस्त किया कि गुरुवार (11 जून) को होने वाली ओपनिंग सेरेमनी पूरी तरह सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न होगी।

क्यों हो रहा है विरोध? गुरुवार के मैच पर संकट का साया

मेक्सिको के शिक्षकों के एक बड़े संघ ने सरकार से वेतन वृद्धि और पेंशन सुधारों की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे गुरुवार को मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले उद्घाटन मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। शिक्षकों की राजधानी में प्रवेश कर रहे

इस मांग को अयोतज़िनापा शिक्षक कॉलेज के उन सैकड़ों छात्रों का भी समर्थन मिल रहा है, जो साल 2014 में लापता हुए 43 छात्रों के मामले में न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

शहर में तनाव का माहौल, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

राजधानी मेक्सिको सिटी की स्थिति इस समय संवेदनशील बनी हुई है। सोमवार को सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के एक बस काफिले से 59 देशी विस्फोटक उपकरण (क्एऊर) बरामद किए, जिसकी पुष्टि पुलिस ने सोशल मीडिया पर की है। इससे पहले पिछले हफ्ते ऐतिहासिक जोकालो स्क्वायर के पास पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा था, जहां वर्ल्ड कप के लिए एक बड़ा फैन जोन और स्क्रीन लगाई गई है।

व्यापार और पर्यटन प्रभावित, बातचीत का दौर जारी

प्रदर्शनकारियों ने डाउनटाउन इलाके में लगीं फुटबॉल खिलाड़ियों की प्रतीकात्मक मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया है। सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने ऐतिहासिक चौकों और रास्तों को लोहे के भारी बैरिकेड्स से बंद कर दिया है।

वर्ल्ड कप के ठीक पहले शहर के मुख्य हिस्सों में प्रदर्शनकारियों के तंबू (टेंट कैंप) लगने से स्थानीय व्यापार ठप हो गया है और विदेशी पर्यटक असमंजस में हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बैरिकेड्स के कारण रास्ते बंद होने से ग्राहक और पर्यटक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

दूसरी ओर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। राष्ट्रपति शीनबाम की सरकार ने पेंशन प्रशासन के लिए एक नई सरकारी कंपनी बनाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन पुरानी पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह बहाल करने से इनकार कर दिया है।